>

Title: Need to set water-pumps to drain out flood water in Hamirpur, Mahoba and Banda district in Uttar Pradesh.

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): सभापति जी, मुझे यहां से बोलने की इजाजत दे दी जाए।

सभापति महोदय : आप खुद कानून की व्याख्या करते हैं फिर भी, चलिये ठीक है।

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं तीन जनपदों हमीरपुर, महोबा और बांदा का एमपी हूं। हमीरपुर की पूरी तहसील जलमग्न है और बांदा में तिनवारी जो मेरा क्षेत्र है वह भी जलमग्न है। करीब 300 से ज्यादा गांव के घर गिर गये हैं। करीब 50 लाख हैक्टेयर लैंड जलमग्न है। मेरा कहना यह है कि राज्य सरकार क्या कर रही है? वह केवल यह कर रही है कि डीएम को कह दिया गया है। हमीरपुर की एक माननीय महिला डीएम है और ऐसे ही दूसरी जगहों पर हैं। वे सिर्फ चना और खाना बंटवा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी स्थाई तौर पर व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति महोदय : आपकी डिमांड क्या है?

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं डिमांड बता रहा हूं। इसमें जो पानी रिसीट कर गया है वह 15-15 दिन तक दो फीट तक घरों में रहता है। अगर वहां 25-30 पम्प एक गांव में दो के हिसाब से लगा दिये जाएं तो पानी दो दिन में निकल जाएगा। उससे घर गिर रहे हैं। बाढ़ चली गयी है, पानी भी निकल गया है लेकिन दो-दो फीट का पानी घरों के अंदर है और वह दो महीने तक रहेगा।

सभापति महोदय : यह जिला प्रशासन का विषय केन्द्र के प्रति कैसे है? जो आपने प्रश्न उठाया है, मैंने केन्द्र के विषय के लिए आपको टाइम दिया है।

श्री विजय बहादुर सिंह : जिला प्रशासन का कहना है कि उनके पास पैसे नहीं हैं।

सभापति महोदय : आप यहां उन्हीं सवालों को उठाए जिनके लिए केन्द्र सरकार उत्तरदायी होती है।

श्री विजय बहादुर सिंह : मुझे मालूम है कि स्टेट सब्जैक्ट और सेंट्रल के सब्जैक्ट्स क्या हैं?

सभापति महोदय : और कंकरेंट सब्जैक्ट्स भी।

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं कहना चाहता हूं कि जब भी बाढ़ आये तो एक कमेटी जिसका चेयरमैन वहां का सांसद हो और वह इसका आंकलन करके बताए कि क्या करना है। जैसे पूरी फसल नष्ट हो गयी तो दो साल के बाद पता चलेगा कि 500-500 रुपये के चैक आ गये। मैं कह रहा हूं कि इसका आंकलन कर दिया जाए और जाड़े की फसल आने के पहले उनका नुकसान उन्हें दे दिया जाए।

तीसरा बात यह है कि उसका जो भी ऋण हो वह माफ कर दिया जाए। वहां के लोगों की तो बहुत डिमांड है लेकिन हमने आंकलन किया है कि 30 करोड़ रुपया यहां से जाए।

सभापति महोदय : ठीक है, आपकी बात आ गयी है धन्यवाद। आप एक पत्र भी राज्य सरकार को लिखिये, मैमोरेंडम सब्मिट करने के लिए कि एक्चुअल कितना लॉस है। यदि आप चाहते हैं कि एक्चुअल लॉस दिया जाए तो उन्हें पत्र लिखिये। जब तक राज्य सरकार ज्ञापन नहीं देगी तब तक भारत सरकार की तरफ से कोई टीम नहीं जा सकती है। श्री सी. राजेन्द्रन, आप बोलिये।